



अपने आप में एक रेकार्ड

बेस्ट पैकेज के आंकड़ों से थोड़ा हटकर देखें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कई इंडिया बेस्ड स्टार्टअप्स और कंपनियां टॉप रिक्लूटर के रूप में उभरी हैं। महामारी शुरू होने के बाद से ही तरह-तरह के निराशाजनक हालात से जूझते यूथ के लिए ये खबरें संजीवनी का काम कर सकती हैं।

नवीन पंडित।।

देश के आईआईटी संस्थानों से इस बार प्लेसमेंट को लेकर अच्छी खबर आ रही है। महामारी और लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री को मंदी की जो मार झेलनी पड़ी, उसका सीधा असर पिछले साल इन संस्थानों से होने वाले प्लेसमेंट पर दिखा था। मगर इस बार सूरत पूरी तरह से बदली हुई है। प्लेसमेंट के पहले हफ्ते में ही कई रेकार्ड टूट चुके हैं। कई संस्थानों में हजार ऑफरों की संख्या पांचवें-छठे दिन ही पार कर गई। कई आईआईटी में 50 के आसपास स्टूडेंट्स एक करोड़ से ऊपर का पैकेज पाने में सफल रहे। आईआईटी दिल्ली में तो यह संख्या 60 पहुंच गई है। वह भी केवल इंटरनेशनल रोल के लिए नहीं, डोमेस्टिक रोल के

लिए भी।

ध्यान रहे, इंटरनेशनल रोल के लिए एक करोड़ से ऊपर के पैकेज पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन घरेलू भूमिका के लिए ऐसा पैकेज पहली बार मिला है। खास बात यह है कि प्लेसमेंट की स्थिति इस साल न केवल पिछले साल के मुकाबले बल्कि पूर्व महामारी यानी 2019 में देखी गई स्थिति से भी बेहतर है। कई मामलों में इसने अब तक के सारे रेकार्ड तोड़ दिए हैं। उदाहरण के लिए आईआईटी बॉम्बे में इस बार ग्रेजुएशन बैच ने पहले छह दिनों में ही 1200 ऑफर पाए, जो अपने आप में एक रेकार्ड है। अन्य संस्थान भी पीछे नहीं हैं। आईआईटी रुड़की में इस बैच को अब तक मिले ऑफर की संख्या 1,171

है, जो पिछले साल दिसंबर में दर्ज किए गए ऑफर से लगभग दोगुना है। अब तक के ट्रेंड को देखते हुए जानकारों का कहना है कि प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी होने तक इस साल मिलने वाली नौकरियां पिछले कई वर्षों के मुकाबले ज्यादा होंगी। बेस्ट पैकेज के आंकड़ों से थोड़ा हटकर देखें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कई इंडिया बेस्ड स्टार्टअप्स और कंपनियां टॉप रिक्लूटर के रूप में उभरी हैं। महामारी शुरू होने के बाद से ही तरह-तरह के निराशाजनक हालात से जूझते यूथ के लिए ये खबरें संजीवनी का काम कर सकती हैं। बेशक यह



केवल आईआईटी संस्थानों के प्लेसमेंट से जुड़ी खबरें हैं, जहां तक यूथ की बहुत छोटी सी संख्या पहुंचती है, लेकिन फिर भी यह इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड का संकेत दे रही हैं। हालांकि कई देशों में कोरोना के नए सिरे से बढ़ते मामले और खासकर इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस चिंता का कारण बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम इस खतरे के साथ जीना सीख रहे हैं। इसलिए अगर हालात हद से ज्यादा नहीं बिगड़े तो उम्मीद यही है कि इंडस्ट्री का यह ट्रेंड जारी रहेगा। इस लिहाज से आईआईटी संस्थानों के जरिए आई पॉजिटिविटी की यह लहर युवाओं में उत्साह का संचार करते हुए मौजूदा माहौल में एक नए दौर का प्रस्थान बिंदु साबित हो सकती है।

संकल्प एवं शरीर

अशोक वोहरा।
धर्म एक साझा ज्ञान है क्योंकि समारोह और सांप्रदायिक परंपराएं एक ही धर्म के विश्वासियों के समुदाय में सामंजस्य के कार्य को पूरा करती हैं। बिना बीज के सृजन नहीं होता है। मन के संकल्प एवं शरीर के पुरुषार्थ के बिना कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। ईश्वर का दूसरा नाम कामेश्वर है एवं उनकी सहचरी कामेश्वरी है। हम अपने संकल्प वृ विकल्प के द्वारा जो कर्म करते हैं, उसका कारण कामनाएं हैं। कामनाएं ही हमें तृप्त करती हैं। कामनाओं की पूर्णता वृ सहभागिता का परिणाम है। साथी हाथ बढ़ाना की फिलोसॉफी, जिसके मूल में दया भावना काम कर रही है। यह स्पष्ट है कि देवताओं का स्वर्ग कामनाओं की पराकाष्ठा है, उदाहरण स्वरूप कामधेनु गाय, कल्पतरु वृक्ष सभी कामनापूर्ति का माध्यम हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

योजनाओं का लाभ

जमीनी हकीकत की पड़ताल करने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर करने का भरपूर प्रयास कर रही है और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी संध अब तक नहीं लगा पाई है। बीजेपी का कुछ वोट कटा है, लेकिन केंद्र और राज्य की लोकलभावन योजनाओं ने बहुत गहरा असर छोड़ा है और बहुत से ऐसे मतदाता बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, जो पहले विपक्षी दलों से जुड़े हुए थे। लखनऊ में ही मजदूरी करने वाली सुनीता लोधी भी इन्हीं योजनाओं की बात करती हैं। बीजेपी जानती है कि अति पिछड़े वर्ग का समर्थन यदि खिसका तो सत्ता उसके हाथ से खिसक जाएगी। लखनऊ के ही सहादतगंज मोहल्ले के रहने वाले राजेश कश्यप कहते हैं कि इस सरकार ने जो मदद की है, कोई कर नहीं सकता। इसलिए वह फिर से एक बार इसी सरकार को लाना चाहते हैं। क्या होगा इस चुनाव में? सीतापुर के अटरिया के लल्लन प्रजापति इस सवाल का सीधे जवाब नहीं देते कि इन चुनावों में क्या होगा, लेकिन बताते हैं कि श्रमिक कार्ड बना था और खाते में एक हजार रुपये आया है। मोदी और योगी कुछ सहायता कर तो रहे हैं। अनाज मिल रहा है। पहले तो सारा अनाज कोटेदार ठेकेदार ही हड़प जाते थे। उसी की बदौलत वह चुनाव परिणाम आने पर राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्य में डाल देती थी। विपक्षी दल, विशेषकर समाजवादी पार्टी इस वर्ग पर गहरी नजर जमाए हुए है। अति पिछड़े वोटों के लिए राजनीतिक दाव-पेच तीखे होते जा रहे हैं। विपक्षी दलों के लिए यह लड़ाई आसान नहीं है।

वास्तव में उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब अति पिछड़ों के वोट पर सिमट गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों का समर्थन बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ था।

दिव्यकत वाले दो साल

बृजेश शुक्ल।।

लखनऊ के पास काकोरी के टिकरिया गांव में क्षेत्र समिति के सदस्य राम प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वह बीजेपी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण कमल को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट देने के पीछे न स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ना ही कोई अन्य नेता। उधर, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उन्होंने 2017 में बीएसपी का साथ छोड़ा तो मायावती 19 सीटों पर सिमट गई और अब बीजेपी से अलग हुए हैं तो वह भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। वास्तव में उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब अति पिछड़ों के वोट पर सिमट गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों का समर्थन बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ था। लेकिन इस बार विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी को लगता है कि अति पिछड़ा वोट उसके पाले में आ सकता है। इसके लिए वह अति पिछड़ों के कई नेताओं को अपनी ओर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ना और अखिलेश यादव से मिलना इसी रणनीति का हिस्सा है।

वैसे, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग ही निर्णायक साबित होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के



पांच वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस दौरान कोरोना महामारी ने आम लोगों के सामने गंभीर संकट पैदा किया। इस दौरान बहुत से लोगों का रोजगार गया। बड़ी संख्या में पलायन हुआ। किसान आंदोलन हुआ। आवारा पशु किसानों के सामने संकट बने रहे। विपक्ष का मानना है कि इन सब वजहों से लोग योगी सरकार से नाराज हैं और इस चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा योगी के पक्ष में शुरू किया गया चुनावी अभियान भी बीजेपी को बचा नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी पहले से ही अति पिछड़ों के बीच लोकप्रिय रही है, लेकिन 2014 में अति पिछड़ा मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा जुड़ा कि चुनाव-दर-चुनाव उन्हीं के लिए वोट करता रहा। विपक्षी दलों को लगता है कि इस बार सत्ता विरोधी रुझान का असर पड़ा है और अति पिछड़े वर्ग के लोग भी योगी सरकार को हराने में लगेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वे सारे प्रयास कर रहे हैं, जिससे अति पिछड़े वोट को अपनी

झोली में डाल सकें। उन्नाव जिले के नवाबगंज के रहने वाले संतराम सचान कहते हैं, 'पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार साइकिल के साथ जाऊंगा।' क्या वास्तव में गांव में भी ऐसा बदलाव हो रहा है या सिर्फ कुछ लोग बदल रहे हैं? इस पर उनका जवाब है, 'बहुत से लोग अभी भी मोदी के साथ हैं। लेकिन उनका अपना मत है और हमारा अपना।' इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 2 वर्षों में लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और अति पिछड़े वर्ग में एसपी ने भी संघमारी की है। लेकिन जमीन एक और कथा चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं ने तमाम समीकरण बदल डाले हैं। कानपुर जिले के महाराजपुर के श्री राम कुशवाहा कहते हैं कि नेताओं के अपने स्वार्थ हैं और आम आदमी के अपने हित। वह बताते हैं कि नेता नगरी के पास पैसे की कमी नहीं है। उनकी लड़ाई टिकट और सत्ता के लिए है और वह अपने ढंग से निर्णय लेते हैं। जबकि गांव में बैठा हुआ गरीब इस बात पर निर्णय ले रहा है कि सरकार से उसे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। यदि मिल भी रहा है तो क्या वह उसके लिए पर्याप्त है? केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं का लाभ वैसे तो पूरे समाज को हुआ है, लेकिन सर्वाधिक लाभ अति पिछड़ों और दलितों को हुआ। इसका असर भी दिख रहा है।

सूचीक नवताल-5381									
4	6	3	8	9	7				
1	9	6	5	4					
4	5		8						
2	5	4	6	1					
3		1	7						
	3								
5	9	7	2	6					
7	6	4	3	9	2				

अपना ब्लॉग

प्रबुद्ध वर्ग को पहचानो
मोहना खैर, उपर्युक्त परिदृश्य इसलिए सामने रखा गया ताकि यह समझा जा सके कि धर्म संसद से ही देश में खतरा पैदा हुआ है या यहाँ खतरनाक तत्व पहले से मौजूद हैं। अब एक और गंभीर सवाल का जायजा लिया जाना चाहिए कि क्या प्रबुद्ध वर्ग ने वाकई में देश की एकजुटता के खतरे से चिंतित होकर धर्म संसद पर कार्रवाई की मांग की है? ध्यान रहे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (एन।ए।) के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों ने सामाजिक एकता को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया, उसकी कल्पना भी मुश्किल है। सीएए को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ प्रचारित करने वाला वर्ग कौन है? किसने यह जताया और बताया कि सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ जाएगी? किसने इस अफवाह की आड़ में उन मुसलमानों को हिंसा का तांडव करने का मौका दिया जो देश को जलाने का कोई ना कोई बहाना ढूँढते रहते हैं? इन सबका जवाब है— वही प्रबुद्ध वर्ग जो आज धर्म संसद में कुछ वक्ताओं के बयानों से देश को छिन्न-भिन्न होने का खतरा भांप रहा है।

